24/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **तमिलनाडु, केरल में नीलगिरी की गिनती की जाएगी 29 अप्रैल (24 अप्रैल) से एक समकालिक सर्वेक्षण में तहर (GS PAPER III: पर्यावरण)**
2. **कई हिमनदी झीलों का विस्तार, भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों की इसरो छवियां दिखाता है (24 अप्रैल) (GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)**
3. **नईमा खातून एएमयू की पहली महिला वीसी बनीं (24 अप्रैल) (राज्य प्रारंभिक)**
4. **जंक फूड को बाहर निकालें, स्वस्थ भोजन की थाली वापस लाएँ (24 अप्रैल) (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)**
5. **भविष्य का बीमा करना: स्वास्थ्य बीमा और नागरिकों की विस्तृत जनसांख्यिकी पर (24 अप्रैल) (GS PAPER I: सोसायटी)**
6. **कम गरीब और अधिक समान देश की ओर (24 अप्रैल) (GS PAPER III: असमानता)**
7. **पीएमएवाई-यू योजना का अवलोकन (24 अप्रैल) (GS PAPER III: आवास)**

PatrioticIAS

तैयार करने के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (24 अप्रैल)

- एडुटेक संगठन MiTran ग्लोबल शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य सकारात्मक कक्षा वातावरण तैयार करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- प्रशिक्षण सत्र 27 अप्रैल और 4 मई को होंगे।
- इसे शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों और शैक्षिक पेशेवरों सहित सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- लक्ष्य एक ऐसा सीखने का माहौल बनाना है जो छात्रों की सहभागिता, सीखने के परिणामों और समग्र कल्याण को बढ़ाए।
- द हिंदू इन स्कूल इस आयोजन का मीडिया पार्टनर है।
- सत्रों में शिक्षा में सकारात्मकता की शक्ति को समझना, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, कक्षा प्रबंधन तकनीकों को लागू करना और सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे विषय शामिल होंगे।

वक्ताओं की विस्तृत श्रृंखला

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के मुख्य वक्ता शामिल होंगे।
- मुख्य वक्ताओं में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की निदेशक नीता बाली; अन्ना-करिन बर्ग, ड्रोटिंग ब्लैंकास जिमनासीस्कोला , स्वीडन से शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण रणनीतिकार; विद्याशंकर गुरु, MiTran

ग्लोबल के सह-संस्थापक और मुख्य विज़न अधिकारी; नेहा शर्मा, सीबीएसई की पूर्व उप सचिव; करेन वैगनन, अटलांटा में टीचिंग अवर यूथ के संस्थापक; डेनिस थॉम्पसन शियरर, फ्लोरिडा के एक स्कूल मनोवैज्ञानिक; चित्रकला रामचंद्रन, चेन्नई पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल; कविता बाजपेयी, एक शिक्षा प्रर्वतक; और अंजलि राजदान, मेलुहा इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद में शिक्षाविदों की निदेशक।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीतियाँ प्रदान करना है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण खुले हैं और mitranglobal.com/page/ccm पर किए जा सकते हैं।

तमिलनाडु, केरल में नीलगिरी की गिनती की जाएगी 29 अप्रैल (24 अप्रैल) से एक समकालिक सर्वेक्षण में तहर (GS PAPER III: पर्यावरण)

नीलगिरि तहर (नीलगिरिट्रैगस) । हिलोक्रियस)

- **तमिलनाडु का राज्य पशु :** द नीलगिरि तहर एक स्थानिक पर्वत अनगुलेट है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है।

नीलगिरि तहर

- **पर्यावास:** इसका प्राकृतिक आवास भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट का पर्वतीय शोला-घास का पारिस्थितिकी तंत्र है। वे आम तौर पर ऊंचाई वाले, ऊबड़-खाबड़ इलाकों में पाए जाते हैं।
- **उपस्थिति:**
  - छोटे, मोटे फर के साथ गठीला शरीर
  - पुरुषों में एक प्रमुख अयाल।
  - नर और मादा दोनों के सींग छोटे, घुमावदार होते हैं।
- संरक्षण **स्थिति:** नीलगिरि तहर को इसकी सीमित सीमा और इसके आवास के लिए खतरों के कारण IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **धमकी:**
  - पर्यावास हानि और विखंडन
  - अवैध शिकार
  - पशुधन से प्रतिस्पर्धा
  - आक्रामक उपजाति
- **संरक्षण के प्रयासों:**

- संरक्षित क्षेत्र: वन्यजीव अभयारण्यों और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जैसे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना।

मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान

- समुदाय-आधारित संरक्षण पहल
- आबादी की निगरानी करना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना

- नीलगिरि तहर की शुरुआत के पांच महीने बाद , तमिलनाडु अपने राज्य पशु की आबादी का अनुमान लगाने की तैयारी कर रहा है।
- तमिलनाडु और केरल के वन विभाग 29 अप्रैल से शुरू होने वाली तीन दिवसीय सिंक्रनाइज़ जनगणना आयोजित करने के लिए सहयोग करेंगे।
- पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि माउंटेन अनगुलेट की आबादी का अनुमान लगाने के लिए बाउंडेड काउंट और डबल ऑब्जर्वर तरीकों को नियोजित किया जाएगा।
- सर्वेक्षण में लगभग 700 लोग भाग लेंगे।
- यह जनगणना पहली बार नीलगिरि के लिए इतने बड़े पैमाने पर, संगठित और वैज्ञानिक सर्वेक्षण आयोजित कर रही है भारत में तहर .
- सर्वेक्षण का उद्देश्य जनसंख्या अनुमान और परियोजना प्रबंधन के लिए मूल्यवान आधारभूत डेटा प्रदान करना है।
- केरल में एराविकुलम और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो नीलगिरि के साथ निवास स्थान साझा करते हैं तमिलनाडु में तहर को भी जनगणना में शामिल किया जाएगा।

वही तरीका

- नीलगिरि के लिए तमिलनाडु की तरह ही गिनती के तरीकों का इस्तेमाल करेंगी तहर जनगणना.
- वे तमिलनाडु से सटे तहर आवासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बड़ी तहर आबादी वाले निरंतर पैच को कवर करेंगे।
- नीलगिरि तहर खड़ी और चट्टानी इलाकों वाले पर्वतीय घास के मैदानों को पसंद करते हैं, जो समुद्र तल से 300 से 2,600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के 2015 के एक अध्ययन में 3,100 से कुछ अधिक नीलगिरि का अनुमान लगाया गया था तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाटों में, उत्तर में नीलगिरि से लेकर दक्षिण में कन्नियाकुमारी पहाड़ियों तक खंडित आवासों में तहर ।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान और प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन जनसंख्या गणना के लिए वैज्ञानिक और सटीक तकनीक विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

कई हिमनदी झीलों का विस्तार, भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों की इसरो छवियां दिखाता है (24 अप्रैल) (GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)

PatrioticIAS

हिमानी झीलें

- **गठन:** हिमनद झीलें पानी के भंडार हैं जो हिमनद गतिविधि से बनते हैं। इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जा सकता है:
    - **कटाव:** ग्लेशियर परिदृश्य में गड्ढे बनाते हैं, जो बर्फ के पीछे हटने के बाद पानी से भर जाते हैं।
    - **मोराइन:** चट्टान और मलबे (मोरेन) के हिमनद जमा घाटियों को बांध सकते हैं, जिससे झीलें बन सकती हैं।

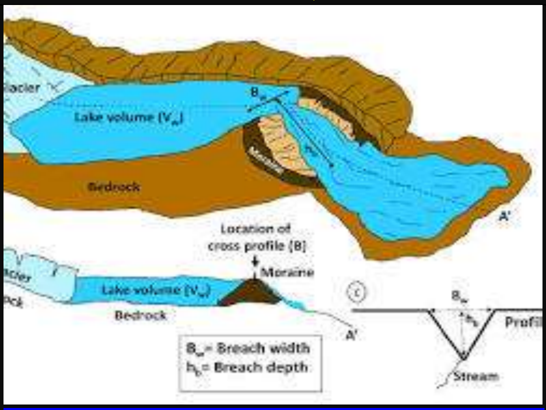

-
    - **बर्फ की रुकावट:** पीछे हटते ग्लेशियर के पिघलते टुकड़े आंशिक रूप से दब सकते हैं, जिससे गड्ढे ('केटल होल') बन सकते हैं जो पानी से भर जाते हैं।

हिमानी झीलों के प्रकार

- **टार्न:** पर्वतीय घाटियों में हिमनदी कटाव से बनी छोटी झीलें।
- **पैटरनोस्टर झीलें:** हिमनदी घाटी में बनी झीलों की एक श्रृंखला, जो एक जलधारा से जुड़ी होती है।
- **मोराइन-बाँधित झीलें:** बड़ी हो सकती हैं और अक्सर ग्लेशियरों के तल पर स्थित होती हैं।
- **सुप्राग्लेशियल झीलें:** ग्लेशियरों की सतह पर ही बनती हैं ।

वितरण: हिमनद झीलें दुनिया भर में वर्तमान या पिछले हिमनद वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, विशेष रूप से हिमालय, एंडीज़ और आल्प्स जैसी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में।

महत्व और चिंताएँ

- **मीठे पानी के भंडार:** हिमनद झीलें मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र और मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर के ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। यह तेजी से पिघलने से मोराइन-बांधित झीलें अस्थिर हो सकती हैं और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) का कारण बन सकती हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** ग्लेशियल झीलों की निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना जीएलओएफ के जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हिमानी झीलों में परिवर्तन:

- 1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी घाटियों को कवर करने वाली दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी हिमनद झीलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाती है।
- 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 हिमनदी झीलों का 1984 के बाद से उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- विशेष रूप से, इनमें से 130 झीलें भारत के भीतर स्थित हैं, जिनमें 65 सिंधु में, 7 गंगा में और 58 ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में हैं।
- विस्तारित झीलों में, सबसे अधिक संख्या मोराइन-बांधित (307) है, इसके बाद क्रमशः कटाव (265), अन्य (96), और बर्फ-बांधित (8) हिमनदी झीलें हैं।

- उपग्रह-व्युत्पन्न दीर्घकालिक परिवर्तन विश्लेषण हिमनद झील की गतिशीलता को समझने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा, क्या आपकी माफी आपके विज्ञापनों जितनी बड़ी थी (24 अप्रैल)

पतंजलि आयुर्वेद में सुप्रीम कोर्ट की जांच :

- सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव द्वारा सह-स्थापित पतंजलि आयुर्वेद से हर्बल दवाओं के लिए उनके सामान्य फ्रंट-पेज विज्ञापनों की तुलना में प्रकाशित माफी के आकार और लागत के बारे में सवाल किया।
- पतंजलि, रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ, अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में आपत्तिजनक और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, जबकि पिछले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विज्ञापनों को रोकने का वचन दिया गया था।
- अदालत ने उनकी पिछली माफ़ी पर असंतोष व्यक्त किया और फटी हुई प्रतियों के बजाय उन मूल समाचार पत्रों को देखने की मांग की जहां माफ़ीनामा प्रकाशित हुआ था।
- तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि माफीनामा 67 अखबारों में प्रकाशित किया गया था, जिसकी कीमत "दसियों लाख" थी।
- अदालत ने रोहतगी को मूल कागजात दाखिल करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया।
- अदालत ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों से नियम 170 को हटाने के लिए आयुष मंत्रालय से भी सवाल किया, जो आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित था।
- सरकार के विशेषज्ञ निकाय ने नियम 170 की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने इसे हटा दिया, जिससे अदालत को स्पष्टीकरण मांगना पड़ा।
- पतंजलि ने अपने विज्ञापन जारी रखने के लिए नियम 170 की अनुपस्थिति को एक बहाना बताया और दावा किया कि आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ शेष कानून "पुराने" हैं।
- अदालत ने मामले में आयुष के तहत लाइसेंसिंग अधिकारियों और दवा नियंत्रकों को भी शामिल किया।

नईमा खातून एएमयू की पहली महिला वीसी बनीं (24 अप्रैल) (राज्य प्रारंभिक)

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर **नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है।** एक सदी पुरानी **कांच की छत को तोड़ना** ।
- इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एएमयू और नेतृत्व पदों पर महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
- प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने के भाजपा सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
- लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से कुछ ही दिन पहले नियुक्ति का समय उल्लेखनीय है और इसके महत्व को बढ़ाता है।

PatriotIAS

- नियुक्ति कुछ समय से लंबित थी और समुदाय में एएमयू कुलपति के महत्व को देखते हुए इसकी घोषणा को मुस्लिम समुदाय के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों का महत्वपूर्ण उल्लंघन (24 अप्रैल)

- अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी 2023 मानवाधिकार रिपोर्ट (एचआरआर) जारी की, जो विभिन्न देशों में मानवाधिकार प्रथाओं की जांच करती है।
- रिपोर्ट ने भारत में कई मानवाधिकारों के हनन की "विश्वसनीय रिपोर्ट" को चिह्नित किया।
- इन दुर्व्यवहारों में **न्यायेतर हत्याएं, जबरन गायब करना, मनमानी गिरफ्तारी या हिरासत, जबरन बयान के लिए यातना, और इंटरनेट शटडाउन और अवरुद्ध दूरसंचार के बार-बार उदाहरण शामिल हैं।**
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में नागरिक समाज कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की निगरानी के साथ-साथ जातीय और जातीय अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले अपराधों का भी उल्लेख किया गया है।
- इसने कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच जातीय संघर्ष के फैलने पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मानवाधिकारों का हनन हुआ।
- रिपोर्ट में मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए न्यूनतम विश्वसनीय कदम या कार्रवाई करने के लिए सरकार की आलोचना की गई।

न्यायेतर हत्याएँ

- 2023 मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में कई मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें मनमानी या गैरकानूनी हत्याएं, न्यायेतर हत्याएं भी शामिल हैं।
- 2016 और 2022 के बीच, भारत में न्यायेतर हत्याओं के 813 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक संख्या छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है।
- "अंतरराष्ट्रीय दमन" पर एक खंड में, रिपोर्ट में पत्रकारों, प्रवासी सदस्यों, नागरिक समाज कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ सरकारी दमन का उल्लेख किया गया है।
- सिख कनाडाई नागरिक हरजीत सिंह निज्जर के मामले का हवाला देते हुए अन्य सरकारों और प्रवासी समुदायों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि भारत सरकार ने प्रतिशोध के लिए अन्य देशों में व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा या धमकियों का इस्तेमाल किया है।
- रिपोर्ट में मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ धमकियों और हिंसा की कई रिपोर्टों के साथ, 2017 और 2022 के बीच एफसीआरए प्रावधानों के तहत 1,827 गैर-लाभकारी संघों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का उल्लेख किया गया है।
- ऐसी विश्वसनीय रिपोर्टें हैं कि आतंकवादी समूहों ने मवेशियों के परिवहन या वध के लिए मुसलमानों और दलितों की हत्या कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सतर्कता के ऐसे कृत्यों को कम करने के लिए 2018 में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एलएएचडीसी लेह

- **विकेंद्रीकृत शासन निकाय:** भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्वशासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम के तहत 1995 में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना और निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तर पर सौंपना।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **योजना एवं विकास:** बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करता है।
- **वित्तीय संसाधन:** केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा आवंटित धन का प्रबंधन करता है और करों और शुल्क के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाता है।
- **विषय वस्तुएँ:** अनेक विषयों पर शक्ति का प्रयोग करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - भूमि उपयोग
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य
  - स्वच्छता
  - पशुपालन
  - सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामले
  - शिक्षा
  - सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

संरचना

- **निर्वाचित परिषद: इसमें** एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 30 पार्षद शामिल होते हैं। अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सरकार द्वारा चार अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जाता है।
- **कार्यकारी परिषद:** एक मुख्य कार्यकारी पार्षद (सीईसी) की अध्यक्षता में, अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा सहायता प्राप्त। कार्यकारी परिषद LAHDC के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

जीका, डेंगू वायरस के खिलाफ नए प्रकार की मेजबान रक्षा का पता चला (24 अप्रैल)

- कुछ वायरस, जैसे **जीका, डेंगू और चिकनगुनिया, लार और वीर्य जैसे शारीरिक तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं लेकिन मौखिक या यौन रूप से नहीं फैलते हैं।**
- वैज्ञानिक वर्षों से इस घटना से हैरान हैं।
- एक शोध दल ने अंततः यह समझाया है कि शारीरिक तरल पदार्थों में मौजूद ये वायरस आवश्यक रूप से उन मार्गों से क्यों नहीं फैलते हैं।
- 29 मार्च, 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि सीओवीआईडी -19 हवाई नहीं है, जिससे वैज्ञानिकों में चिंता पैदा हो गई।
- कई वैज्ञानिकों ने ट्वीट की सामग्री पर विवाद करने के लिए डब्ल्यूएचओ से संपर्क किया, और इसे बदनाम करने के लिए सबूत उपलब्ध कराए।
- बाद में यह ट्वीट तथ्यात्मक रूप से ग़लत साबित हुआ, लेकिन WHO लगभग दो वर्षों तक इस पर असंबद्ध रहा।
- वायरस के जीवन चक्र में ट्रांसमिशन एक महत्वपूर्ण घटना है, और इसका अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण रहा है।

PatriotiсIAS

- सफल वायरस ने वर्षों में असाधारण अनुकूलन विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नए मेजबानों तक पहुंच सकें।
- प्रकोप को नियंत्रित करने और प्रभावी निवारक उपाय विकसित करने के लिए वायरस संचरण को समझना आवश्यक है।

वायरस शरीर के अंदर क्या करता है?

- अधिकांश मानव वायरस शारीरिक तरल पदार्थों में मौजूद होने से फैलते हैं जो बाहरी वातावरण के संपर्क में आते हैं, जिससे एक नए मेजबान में संचरण की सुविधा मिलती है।
- एक बार नए मेजबान के अंदर, वायरस को संक्रमित करने के लिए विशिष्ट कोशिकाओं को लक्षित करना होगा। इस चयनात्मकता को ट्रॉपिज़्म के रूप में जाना जाता है।
- वायरस की सतह पर प्रोटीन होते हैं जो मेजबान कोशिकाओं पर रिसेप्टर्स के साथ बातचीत करते हैं। इन रिसेप्टर्स वाली कोशिकाएं संक्रमण के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- उदाहरण के लिए, एचआईवी उन कोशिकाओं को लक्षित करता है जो सीडी4 प्रोटीन का उत्पादन करती हैं, जैसे टी-कोशिकाएं और मैक्रोफेज। SARS-CoV-2 श्वसन पथ और कुछ हृदय कोशिकाओं में पाए जाने वाले ACE2 रिसेप्टर को व्यक्त करने वाली कोशिकाओं को लक्षित करता है।
- वायरल ट्रांसमिशन में वायरस की प्रतिकृति बनाने और उससे लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच एक दौड़ शामिल होती है। इससे पहले कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इसे साफ़ कर दे या मेज़बान संक्रमण का शिकार हो जाए, वायरस फैल जाना चाहिए।
- कुछ वायरस कई प्रकार की कोशिकाओं पर रिसेप्टर्स के साथ सतही प्रोटीन रखने की रणनीति का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को संक्रमित करने और विभिन्न शारीरिक तरल पदार्थों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है, जिससे त्वरित संचरण की सुविधा मिलती है।

पीएस रिसेप्टर क्या है?

- फॉस्फेटिडिल सेरीन (पीएस) एक प्रोटीन है जो मरने वाली कोशिकाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उन्हें नष्ट करने का संकेत देता है ।
- वायरस एपोप्टोटिक मिमिक्री के माध्यम से इस मार्ग का फायदा उठाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विनाश के लिए लक्षित कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए अपनी सतहों पर पीएस व्यक्त करते हैं।
- पीएस रिसेप्टर कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं सहित कई कोशिकाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो इसे वायरस के लिए एक लक्ष्य बनाता है।
- वायरल ट्रांसमिशन का अध्ययन करना, विशेष रूप से पीएस रिसेप्टर का उपयोग करके वायरस के लिए, चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वायरस कई डिब्बों में मौजूद हो सकता है।
- किसी डिब्बे में वायरस की उपस्थिति मात्र उस मार्ग से संचरण की गारंटी नहीं देती है। उदाहरण के लिए, जीका वायरस वीर्य, लार और स्तन के दूध जैसे शारीरिक तरल पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन मौखिक और जननांग गुहाओं में लक्ष्य कोशिकाओं की मौजूदगी के बावजूद मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से फैलता है।

शरीर अपनी रक्षा कैसे करता है ?

- जर्मनी के उल्म यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने जीका और इसी तरह के वायरस के खिलाफ एक नई रक्षा तंत्र की खोज की है।

PatrioticIAS

- नेचर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित, अध्ययन से पता चलता है कि शरीर वायरल संक्रमण को रोकने के लिए शारीरिक तरल पदार्थों में बाह्य कोशिकीय पुटिकाओं का उपयोग कैसे करता है।
- वेसिकल्स वसा से घिरी छोटी संरचनाएं हैं, जिनका उपयोग कोशिकाओं द्वारा कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है।
- कोशिका के बाहर स्रावित बाह्यकोशिकीय पुटिकाओं की सतह पर पीएस प्रोटीन होते हैं, जिनका उपयोग जीका जैसे वायरस संक्रमण के लिए करते हैं।
- ये पुटिकाएं लार और वीर्य में प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिनमें पीएस प्रोटीन होता है, लेकिन रक्त में इनकी सांद्रता कम होती है।
- प्रयोगों के माध्यम से, शोधकर्ताओं ने दिखाया कि पीएस-युक्त वेसिकल्स प्रवेश रिसेप्टर्स के लिए वायरस के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, वायरस को बाहर निकालकर संक्रमण को रोकते हैं।

यह खोज क्या दर्शाती है?

- अनुसंधान समूह ने पाया कि एपोप्टोटिक नकल के लिए पीएस रिसेप्टर का उपयोग करने वाले वायरस, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल, इबोला और वेसिकुलर स्टामाटाइटिस वायरस, बाह्य कोशिकीय पुटिकाओं द्वारा बाधित होते हैं।
- इन पुटिकाओं की उपस्थिति ने उन वायरस की संक्रामकता को प्रभावित नहीं किया जो एचआईवी और SARS-CoV-2 जैसे प्रवेश के लिए PS रिसेप्टर का उपयोग नहीं करते हैं।
- प्रतिरक्षा के हिस्से के रूप में पीएस-लेपित वेसिकल्स की यह खोज वायरल संक्रमण के खिलाफ एक नए प्रकार की रक्षा है।
- हालाँकि चिकित्सीय अनुप्रयोगों की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, यह खोज आगे के शोध के लिए रास्ते खोलती है।
- अध्ययन एक दूरगामी विचार सुझाता है कि मनुष्यों में पीएस युक्त पुटिकाओं ने मच्छर जनित वायरस के विकास को प्रभावित किया होगा।
- यह अनुमान लगाया गया है कि लार या वीर्य के माध्यम से संचारित करने में असमर्थ होने पर ये वायरस अलग-अलग तरीके से फैलने के लिए अनुकूलित हो सकते हैं, जो प्रकृति में अनुकूलन की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है।

जंक फ़ूड को बाहर निकालें, स्वस्थ भोजन की थाली वापस लाएँ (24 अप्रैल) (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)

स्वस्थ और पोषण संबंधी विविध आहार को बढ़ावा देने और सूचित भोजन विकल्प सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार नीतिगत हस्तक्षेप द्वारा समर्थित एक जन आंदोलन की आवश्यकता है।

- भारत एक महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसे " **पोषण संक्रमण " के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक उच्च फाइबर आहार से अधिक प्रसंस्कृत, कैलोरी युक्त पश्चिमी शैली के आहार की ओर** बढ़ रहा है ।

PatrioticIAS

- यह परिवर्तन आर्थिक प्रगति, शहरीकरण और पैकेज्ड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के साथ मेल खाता है, जिन्हें आमतौर पर "जंक फूड" कहा जाता है।
- जंक फूड में विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व कम होते हैं लेकिन कैलोरी, वसा, नमक, चीनी और परिरक्षकों की मात्रा अधिक होती है (उदाहरणों में सॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड और सोडियम नाइट्राइट शामिल हैं)।
- वैज्ञानिक प्रमाण जंक फूड के सेवन को कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, उच्च रक्तचाप, ऊंचे रक्त शर्करा के स्तर, वजन बढ़ने और कैंसर के बढ़ते खतरे से जोड़ते हैं।
- उच्च वसा, नमक और शर्करा (एचएफएसएस) खाद्य पदार्थों के उदाहरण कुकीज़, केक, चिप्स, शर्करा युक्त पेय, इंस्टेंट नूडल्स, डिब्बाबंद फल और बेकरी उत्पाद शामिल करें ।
- जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने में अस्वास्थ्यकर आहार का बड़ा योगदान है भारत में, आबादी का एक बड़ा हिस्सा मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पेट के मोटापे जैसे चयापचय संबंधी विकारों से प्रभावित है।
- "स्वादिष्ट" और "किफायती" आरामदायक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने वाले आक्रामक विज्ञापन , विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं को लक्षित करते हुए , आहार संबंधी आदतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों में पैकेज्ड फूड की खपत का प्रचलन बहुत अधिक है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा रोजाना मीठे पेय पदार्थ और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करता है।
- अति -प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग भारत में तेजी से विकास हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2025-26 तक 535 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है ।

कोर्ट की चिंता

- सुप्रीम कोर्ट (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला (1991), एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (2013), उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (सीईआरसी) बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य मामला (2015)): इस बात पर जोर दिया गया कि खतरनाक खाद्य पदार्थ **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को खतरे में डालते हैं** संविधान का.
- **ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना (पोषण) 2.0** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ भोजन और सक्रिय जीवन शैली को प्राथमिकता दी गई।
- **एफएसएसएआई विनियम** : बच्चों को अस्वास्थ्यकर भोजन से बचाने के लिए स्कूलों के पास एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की प्रतिबंधित बिक्री।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** : उत्पाद की स्वास्थ्यवर्धकता के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए स्वास्थ्य पेय कंपनियों को नोटिस जारी किया।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ: नीतियों के बावजूद, जंक फूड की खपत को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई कठिन बनी हुई है।
- प्रमुख रणनीतियाँ:
  - नियामक प्रवर्तन को मजबूत करें.
  - पोषण शिक्षा कार्यक्रम लागू करें।
  - **खाद्य उद्योग सुधार को प्रोत्साहित करें।**
  - स्वस्थ भोजन के लिए समुदाय-आधारित पहल को बढ़ावा दें।

एक स्पष्ट परिभाषा तैयार करें

- बच्चों को जंक फूड से बचाएं:
  - एफएसएसएआई के पास एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है।
  - बेहतर विनियमन कार्यान्वयन के लिए एचएफएसएस खाद्य पदार्थों को परिभाषित करें।
  - **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** द्वारा स्कूली भोजन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।
- **फ्रंट-ऑफ़-पैक लेबलिंग (FOPL) का उपयोग करें:**
  - उपभोक्ताओं को सूचित भोजन विकल्प चुनने में मदद करता है।
  - भोजन के पैकेटों पर वर्तमान पोषण तालिकाओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
  - बेहतर समझ के लिए सामने "नमक की मात्रा अधिक" जैसे चेतावनी लेबल लागू करें।
- भारतीय पोषण रेटिंग (INR):
  - मसौदा विनियमों में शामिल.
  - अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को पास करने की अनुमति देने वाली स्टार रेटिंग के बारे में चिंताएँ।

स्वस्थ भोजन के लिए सब्सिडी लें

- स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए सकारात्मक सब्सिडी:
  - साबुत खाद्य पदार्थ, बाजरा, फल और सब्जियों को बढ़ावा दें।
  - उन्हें अधिक उपलब्ध और किफायती बनाएं.
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक खपत को प्रोत्साहित करें।

PatrioticIAS

- व्यवहार परिवर्तन अभियान:
    - बच्चों और युवा वयस्कों को लक्षित करें.
    - स्वस्थ खान-पान की आदतों के बारे में शिक्षित करें।
    - जंक फूड के स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालें।
    - स्थानीय एवं मौसमी उपज को बढ़ावा दें।
    - जागरूकता के लिए सोशल मीडिया प्रभावकों का उपयोग करें।
- स्वस्थ आहार की तात्कालिकता:
    - आंदोलन " या लोगों का आंदोलन बनाएं ।
    - स्वस्थ आहार के लिए सार्वजनिक मांग उत्पन्न करें।
    - सूचित भोजन विकल्पों के लिए नीतिगत हस्तक्षेप लागू करें।

भविष्य का बीमा करना: स्वास्थ्य बीमा और नागरिकों की विस्तृत जनसांख्यिकी पर (24 अप्रैल)

(GS PAPER I: सोसायटी)

पात्रता को व्यापक बनाते हुए स्वास्थ्य बीमा को किफायती बनाया जाना चाहिए

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है** । यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों के लिए शीर्ष नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य:

- पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
- भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करना, बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण कार्यों:

- **लाइसेंस जारी करना: बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करना** उनकी वित्तीय सुदृढ़ता और व्यावसायिक योजनाओं का आकलन करने के बाद।
- **विनियमन: उत्पाद डिजाइन, प्रीमियम दरें, सॉल्वेंसी मार्जिन और एजेंट लाइसेंसिंग सहित बीमा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर नियम तैयार करता है।**
- **उपभोक्ता संरक्षण:** पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करता है और बीमा कंपनियों द्वारा उचित उपचार सुनिश्चित करता है।
- **बाज़ार विकास:** बीमा बाज़ार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए नवाचार और बेहतर उत्पाद सामने आते हैं।

संघटन:

- **IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष , पांच पूर्णकालिक सदस्य और भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।**

फ़ायदे:

- **स्थिरता और विकास:** IRDAI का नियामक ढांचा एक स्थिर और बढ़ते बीमा क्षेत्र को बनाए रखने में मदद करता है, निवेश और जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है।

- **बढ़ी हुई पसंद:** आईआरडीएआई नियमों द्वारा बढ़ी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के लिए बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आती है।
- **पारदर्शिता और निष्पक्षता:** IRDAI नियम बीमा उत्पादों में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और पॉलिसीधारकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।

- आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों सहित व्यापक जनसांख्यिकीय लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
- भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, 2050 तक वरिष्ठ आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का अनुमान है कि **2050 तक वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) की आबादी 10% से बढ़कर 30% हो जाएगी।**
- यह जनसांख्यिकीय बदलाव विकसित देशों में देखे गए रुझानों को प्रतिबिंबित करता है, जहां स्वास्थ्य देखभाल और सामर्थ्य तक पहुंच के बारे में चिंताएं महत्वपूर्ण हैं।
- विकसित देशों में, **स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ सरकार द्वारा वित्त पोषित से लेकर पूरी तरह से निजी तक भिन्न होती हैं, लागत अक्सर गुणवत्ता देखभाल में बाधा बनती है।**
- बीमांकिक सिद्धांतों का पालन करते हुए, उम्र के साथ स्वास्थ्य बीमा अधिक महंगा हो जाता है।
- वर्तमान में, **भारत के आर्थिक अभिजात वर्ग का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही व्यापक पारिवारिक स्वास्थ्य योजनाओं का खर्च उठा सकता है।**
- आईआरडीएआई के निर्देश से अधिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन अगर वे अप्राप्य रहेंगी, तो यह अंतर्निहित मुद्दे का समाधान नहीं करेगा।
- भारत का भविष्य अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर निर्भर है, जिसके लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है।
- कुछ दक्षिणी भारतीय राज्यों में, बुजुर्गों के लिए पारंपरिक देखभाल देने वाली संरचना पहले से ही टूट रही है, जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच की आवश्यकता को उजागर करती है।
- स्वास्थ्य बीमा पात्रता के विस्तार के साथ-साथ किफायती स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त सुधार भी होना चाहिए।

अत्यधिक प्रतिबंध: मतदान के समय पर प्रतिबंध

(24 अप्रैल)

मतदान के समय प्रतिबंधों के खिलाफ याचिका सार्वजनिक भागीदारी के बारे में वैध सवाल उठाती है

- कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव अवधि के दौरान लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों को चुनौती दी है।
- **सीआरपीसी की धारा 144** के तहत जारी ये आदेश बिना अनुमति के सभाओं और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं।

PatriotIAS

- नागरिक समाज संगठनों को पता चलता है कि सभाओं के लिए उनके आवेदनों को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, जिससे चुनावों के दौरान सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों की कमी हो जाती है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के व्यापक निषेधात्मक आदेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, विशेषकर मतदाताओं को शिक्षित करने में सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करते हैं।
- अदालत के फैसलों ने चुनाव के दौरान व्यापक प्रतिबंधों की वैधता पर सवाल उठाते हुए धारा 144 की शक्ति को सीमित कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने व्यापक आदेश पारित करने के औचित्य पर चिंता जताई और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को तीन दिनों के भीतर सार्वजनिक बैठकों के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
- इस बात पर बहस चल रही है कि क्या केवल चुनाव ही सार्वजनिक भागीदारी और विवेकाधीन शक्तियों पर व्यापक प्रतिबंध को उचित ठहराते हैं।
- जबकि अधिकारियों का तर्क है कि चुनाव के दौरान वे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के नियंत्रण में हैं, सवाल उठता है कि क्या ईसीआई इस तरह के प्रतिबंधों का समर्थन करता है और क्या वैधानिक शक्तियां उसे हस्तांतरित की जा सकती हैं।

कम गरीब और अधिक समान देश की ओर

(24 अप्रैल) (GS PAPER III: असमानता)

उच्च आर्थिक विकास और असमानता में कमी के दोहरे उद्देश्य केवल मानव विकास में सुधार और गरीबी में कमी के साथ ही प्राप्त किए जा सकते हैं

- **विश्व असमानता लैब, एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र**, ने मार्च में **"भारत में आय और धन असमानता, 1922-2023: अरबपति राज का उदय" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया।**
- पेपर नितिन कुमार भारती, लुकास चांसल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमांची द्वारा लिखा गया था।
- **राष्ट्रीय आय खातों, धन समुच्चय, कर सारणी, समृद्ध सूची और आय, उपभोग और धन पर सर्वेक्षण** सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा को जोड़ती है।
- पेपर का उद्देश्य 1922 से 2023 तक भारत में आय और धन असमानता प्रवृत्तियों का विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करना है।
- यह **अत्यधिक धन के उद्भव और वृद्धि पर केंद्रित है, जिसे अक्सर "अरबपति राज" कहा जाता है।** निर्दिष्ट अवधि के दौरान भारत में।

आय और धन असमानता

- भारत में आय असमानता 2022-23 में अपने चरम पर पहुंच गई है, शीर्ष 1% आबादी को राष्ट्रीय आय का 22.6% प्राप्त होता है, जो पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक है।
- शीर्ष **0.1% आबादी ने लगभग 10% अर्जित किया** इसी अवधि के दौरान भारत में राष्ट्रीय आय का.
- धन असमानता भी महत्वपूर्ण है, शीर्ष **1% के पास 2022-23 में राष्ट्रीय संपत्ति का 40.1% हिस्सा है, जो 1961 के बाद से उच्चतम स्तर है।**
- हिस्सा **1961 में 45% से बढ़कर 2022-23 में 65% हो गया, जबकि निचले 50% और मध्य 40% की हिस्सेदारी में गिरावट आई।**

PathfinderIAS

- 92 मिलियन भारतीय वयस्कों में से लगभग 10,000 व्यक्तियों के पास औसतन ₹22.6 बिलियन की संपत्ति है, जो औसत भारतीय की संपत्ति का 16,763 गुना है।
- हालाँकि भारत की धन असमानता ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जितनी चरम नहीं है, लेकिन 1961 और 2023 के बीच यह तीन गुना बढ़ गई है।
- भारत में आय असमानता वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है, यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया गया है, जो धन असमानता को बढ़ाता है।
- 1960 और 1980 के बीच की अवधि में असमानता में गिरावट देखी गई, लेकिन 1980 के दशक में उदारीकरण की शुरुआत के साथ इसमें वृद्धि शुरू हुई और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के बाद इसमें तेजी आई।
- शीर्ष स्तर की असमानता में वृद्धि, विशेष रूप से धन संकेंद्रण में, 2014-15 के बाद से महत्वपूर्ण रही है, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की तुलना में अधिक असमान समाज बन गया है।
- **1975 तक भारत की औसत आय चीन और वियतनाम के बराबर थी।**
- अगले 25 वर्षों में, चीन और वियतनाम की आय में भारत की तुलना में 35-50% अधिक वृद्धि हुई।
- 2000 के बाद, चीन की आय तेजी से बढ़ी, जो भारत की तुलना में 2.5 गुना हो गई।
- **चीन की वृद्धि व्यापक आधार वाली रही है, जबकि भारत की वृद्धि अत्यधिक आर्थिक असमानता के साथ जुड़ी हुई है।**
- **2022 में, भारत के शीर्ष 1% ने चीन के शीर्ष 1% की तुलना में लगभग 50% अधिक आय अर्जित की।**
- चीन और वियतनाम ने मानव विकास और गरीबी में कमी के माध्यम से असमानता में कमी के साथ-साथ उच्च आर्थिक विकास हासिल किया।
- सतत आर्थिक विकास के लिए मानव विकास में सुधार की आवश्यकता है, जो आर्थिक विकास से पहले होना चाहिए।
- भारत में निरंतर उच्च विकास दर (प्रति वर्ष 7% जीएसडीपी से अधिक) वाले राज्य मानव विकास में अपेक्षाकृत उन्नत थे, जिनमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं।
- झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कम मानव विकास वाले राज्यों में उदारीकरण के बाद प्रति वर्ष 5% से कम की वृद्धि दर दर्ज की गई।

मानव विकास

मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर)?

- **वार्षिक रिपोर्ट:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 1990 से प्रकाशित, एचडीआर मानव-केंद्रित परिप्रेक्ष्य से प्रमुख विकास मुद्दों की जांच करता है।
- **आर्थिक विकास से परे:** यह जीडीपी जैसे पारंपरिक उपायों से आगे जाता है और लोगों की पसंद, स्वतंत्रता और समग्र कल्याण के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **मानव विकास सूचकांक (एचडीआई):** शायद एचडीआर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता, एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो तीन प्रमुख आयामों में किसी देश की उपलब्धि को मापता है:
    - लंबा और स्वस्थ जीवन (स्वास्थ्य)
    - ज्ञान तक पहुंच (शिक्षा)
    - सभ्य जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति जीएनआई)

- **मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2023-2024 में भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है** ।

PatrioticIAS

- पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत **श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से पीछे है** मानव विकास में.
- भारत के लिए आर्थिक विकास मानव विकास में वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुआ है।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; गरीबों को मिलने वाले लाभ के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए।
- मानव विकास में सुधार, क्षमता वृद्धि और गरीबी में कमी के बिना, आर्थिक विकास समावेशी नहीं हो सकता है और इससे असमानता ही बढ़ेगी।
- **आर्थिक असमानता को ध्यान में रखने पर भारत का मानव विकास स्कोर 31.1% कम हो जाता है।**
- जैसे कार्यक्रम **, जो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करते हैं, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अपर्याप्त हैं।**
- सतत और समावेशी विकास रोजगार सृजन के बिना केवल प्रोत्साहनों पर आधारित नहीं हो सकता है।
- यदि असमानता के उच्च स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन सकता है।

पीएमएवाई-यू योजना का अवलोकन (24 अप्रैल) (GS PAPER III: आवास)

- वर्तमान केंद्र सरकार ने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं।
- इसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक **2022 तक सभी के लिए आवास (एचएफए) था** ।
- कार्यक्रम का **उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास प्रदान करना था।**
- इसकी योजना **2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) योजना के तहत बनाई गई थी** ।

PMAY योजना क्या है?

- PMAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसमें वित्तीय योगदान देना होता है।
- योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - **निजी डेवलपर्स की भागीदारी से झुग्गीवासियों** का पुनर्वास ।
  - **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं (सीएलएसएस) के माध्यम से** कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना ।
  - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास।
  - लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के लिए सब्सिडी।

योजना किस प्रकार फलीभूत हुई?

- एचएफए (सभी के लिए आवास) योजना के कथित रूप से पूरा होने के बावजूद अधूरा है।
- अगस्त 2022 में, पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए PMAY-शहरी (PMAY-U) को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
- **केंद्रों में 30 लाख घरों की कमी** होने का अनुमान है ।
- हालाँकि, वास्तविक आंकड़े अधिक कमी का सुझाव देते हैं, **2012 से 2018 तक शहरी आवास की कमी 54% बढ़ गई है।**

PatrioticIAS

- स्वीकृत और पूर्ण खंडों से लगभग 40 लाख घरों की कमी के साथ, पीएमएवाई-यू उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
- **आईएसएसआर (इन-सीटू स्लम पुनर्विकास) विशेष रूप से विफल रहा है, केवल 2,10,552 घरों को मंजूरी दी गई है।**
- रिपोर्टों के अनुसार, **पीएमएवाई-यू ने 80 लाख घर उपलब्ध कराकर केवल 25.15% आवास की कमी को पूरा किया है।**
- यदि शेष स्वीकृत मकानों का निर्माण 2024 तक भी हो जाता है, तो यह केवल **वास्तविक आवश्यकता का लगभग 37% ही पूरा कर पाएगा, जिससे लगभग 2.4 करोड़ घर बिना छत के रह जाएंगे।**
- कम लागत वाले आवास पर पिछले पांच वर्षों में $29 बिलियन से अधिक खर्च करने के बावजूद, "सभी के लिए आवास" एक अधूरा वादा बना हुआ है।

PMAY को क्या दिक्कत हुई?

- PMAY योजना **काफी हद तक निजी क्षेत्र की भागीदारी पर निर्भर करती है** सामाजिक आवास के लिए सार्वजनिक निवेश में अंतर को भरना।
- भारतीय शहरी क्षेत्रों में लगभग 40% (विश्व बैंक के अनुसार, 49%) लोग निर्दिष्ट या अनौपचारिक झुग्गियों में रहते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में आवास की समस्या को संबोधित करना पीएमएवाई की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
- हालाँकि, **झुग्गी-झोपड़ियों की जगहों को निजी खिलाड़ियों को सौंपने वाली कुछ परियोजनाओं के परिणामस्वरूप लंबवत विकास हुआ, जिससे उपयोगिताओं की आवर्ती लागत और रहने की जगह कम होने के कारण निवासियों के लिए अधिक समस्याएं पैदा हुईं।**
- **भूमि स्वामित्व के मुद्दे** , जैसे **कि हवाई अड्डों, रेलवे, या जंगलों के तहत भूमि, ने आईएसएसआर (इन-सीटू स्लम पुनर्विकास) के लिए आवास आवश्यकताओं को संबोधित करना असंभव बना दिया है।**
- आईएसएसआर के लिए योजनाएं अक्सर समुदाय की भागीदारी के बिना सलाहकारों द्वारा तैयार की जाती थीं।
- शहर के मास्टर प्लान और पीएमएवाई-यू के बीच एक अंतर है, **कई शहर सामाजिक आवास के बजाय बड़े पूंजी-गहन तकनीकी समाधानों को प्राथमिकता देते हैं।**
- **पीएमएवाई के निवेश व्यय में केंद्र का योगदान केवल 25% है, जिसमें अधिकांश धन लाभार्थी परिवारों (60%) और राज्य सरकारों (15%) से आता है।**
- पीएमएवाई की वास्तुकला कई क्षेत्रों में सीमित सरकारी भूमिका के साथ, भूमिहीन और गरीबों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करती है।
- **आईएसएसआर के तहत पुनर्वास के लिए पात्र झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार कुल लाभार्थियों का केवल 2.5% हैं।**

भारत ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने की कैसे योजना बना रहा है? (24 अप्रैल)

- 15 मार्च को, केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी।

PatrioticIAS

- इस नीति में भारत में ईवी निर्माण में रुचि रखने वाली कंपनियों के लिए ₹4,150 करोड़ की न्यूनतम निवेश आवश्यकता शामिल है।

नीति क्या निर्धारित करती है?

- केंद्र सरकार की नई नीति का उद्देश्य टेस्ला और बीवाईडी जैसे वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- नीति का मुख्य लक्ष्य स्थानीय बाजार स्थितियों और मांग के अनुरूप वित्तीय रूप से व्यवहार्य तरीके से ईवी के स्थानीय उत्पादन की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाना है।
- नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान $35,000 की न्यूनतम लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य के साथ पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयातित ईवी पर आयात शुल्क को मौजूदा 70% -100% से घटाकर 15% करना है। पांच साल की अवधि, तीन साल के भीतर एक विनिर्माण इकाई की स्थापना पर निर्भर।
- नीति में यह भी बताया गया है कि आयातित ईवी की कुल संख्या पर ₹6,484 करोड़ की कुल शुल्क छूट या किए गए निवेश के आधार पर आनुपातिक राशि - जो भी कम हो - दी जाएगी, जिसमें पांच वर्षों में 40,000 ईवी की अधिकतम आयात सीमा होगी।
- योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, निर्माताओं को न्यूनतम $800 मिलियन का निवेश करना होगा और स्थानीयकरण लक्ष्यों का पालन करना होगा।
- निर्माताओं के पास भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए तीन साल हैं और तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% स्थानीयकरण हासिल करने की उम्मीद है।
- स्थानीयकरण लक्ष्यों या योजना में उल्लिखित न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्माताओं की बैंक गारंटी रद्द की जा सकती है।

घरेलू खिलाड़ियों के बारे में क्या?

- टाटा मोटर्स ने आयात शुल्क कम करने के टेस्ला के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इससे घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निवेश माहौल को नुकसान होगा।
- डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रजत महाजन के अनुसार, अधिकांश भारतीय खिलाड़ी वर्तमान में ईवी बाजार में ₹29 लाख से नीचे के सेगमेंट पर हावी हैं।
- नीति के लाभ, विशेष रूप से आयात शुल्क में 15% की कमी, मुख्य रूप से उच्च-अंत बाजार खंड में उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के पक्ष में होने की उम्मीद है।
- महाजन ने कहा कि यह नीति वैश्विक ईवी खिलाड़ियों और ऐसे खिलाड़ियों के साथ भारतीय संयुक्त उद्यमों (जेवी) के लिए भारत में बिक्री और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक आकर्षक अवसर पैदा करती है।

यह भारतीय बाज़ारों की जरूरतों को कैसे पूरा करता है?

- टेरी के प्रतिष्ठित फेलो आईवी राव भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले वैश्विक खिलाड़ियों के लिए पर्यावरण, सड़कों और उपयोग पैटर्न जैसी स्थानीय स्थितियों पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं।
- डेलॉइट के रजत महाजन का कहना है कि जहां दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में ईवी की पैठ महत्वपूर्ण रही है, वहीं अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज की चिंता और सीमित किफायती उत्पाद विकल्प जैसी चुनौतियों के कारण यात्री वाहनों ने अब तक केवल 2.2% का योगदान दिया है।

PatrioticIAS

- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का सुझाव है कि ईवी के आक्रामक योगदान को समर्थन देने के लिए भारत को 2030 तक लगभग 13 लाख चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता हो सकती है।
- दिनेश अब्रोल, एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विश्वसनीयता, घटकों की स्थायित्व और सेवा समर्थन को संबोधित करने के लिए ईवी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मारुति के साथ साझेदारी में सुजुकी के बढ़ते नियंत्रण का उल्लेख किया, जिससे आयात में वृद्धि हुई।
- अब्रोल इस बात पर जोर देते हैं कि 21वीं सदी में ध्यान न केवल प्रतिस्पर्धी उत्पादों पर बल्कि स्थिरता पर भी होना चाहिए। वह निर्यात के अनुरूप उत्पाद और सिस्टम डिजाइन को निर्देशित करने के लिए घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं , और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त डिजाइन के महत्व पर जोर देते हैं।

मौन के दौरान डिजिटल विज्ञापन अभियानों का विश्लेषण

अवधि (24 अप्रैल)

- बड़े पैमाने पर चल रहे चुनावों के दौरान, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मतदाताओं पर उनके प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
- भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा स्थापित आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया जा रहा है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126, मतदान बंद होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से चुनाव-संबंधी सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाती है।
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि "समान उपकरण" में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
- लोकनीति द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि राजनीतिक दल मौन अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर विज्ञापन अभियानों पर महत्वपूर्ण राशि खर्च करते हैं ।

सोशल मीडिया अभियान

- 17 से 19 अप्रैल, 2024 के दौरान, भाजपा ने Google पर 60,500 विज्ञापन और मेटा प्लेटफ़ॉर्म पर 6,808 विज्ञापन पोस्ट किए, जबकि कांग्रेस ने क्रमशः 1,882 और 114 विज्ञापन पोस्ट किए।
- यह इस बात को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि भारत में इंटरनेट की पहुंच 50% से अधिक है।
- उस अवधि के दौरान Google पर पोस्ट किए गए सभी विज्ञापनों में से, 500 विज्ञापनों (भाजपा और कांग्रेस से 250 प्रत्येक) का एक नमूना विश्लेषण के लिए चुना गया था।
- इस नमूने में, भाजपा के 64 और कांग्रेस के 32 विज्ञापन पहले चरण के मतदान वाले राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों को लक्षित करने वाले पाए गए।
- पहले चरण के मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्येक 50 में से 13 विज्ञापन मौन अवधि के दौरान प्रसारित किए गए थे।
- पहले चरण के चुनाव से पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजनीतिक विज्ञापन देखे गए, जो रणनीतिक प्लेसमेंट का संकेत देते हैं।

PatrioticIAS

- उत्तराखंड के हलद्वानी में विशिष्ट सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण को छोड़कर, अधिकांश कांग्रेस विज्ञापनों ने पहले चरण में मतदान करने वाले राज्यों को लक्षित किया।
- यह डेटा चुनावी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के रणनीतिक समय और लक्ष्यीकरण पर प्रकाश डालता है।

भू लक्ष्यीकरण की रणनीति

- मौन अवधि के दौरान, भाजपा के डिजिटल अभियान ने सटीक स्थान-आधारित लक्ष्यीकरण का प्रदर्शन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पंचायत और कर्नाटक में बेलथांगडी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मतदाता जनसांख्यिकी के संदर्भ में इसके ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में नगीना निर्वाचन क्षेत्र को भी निशाना बनाया।
- हालाँकि, इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया।
- इसके विपरीत, कांग्रेस ने निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय लक्ष्यीकरण से परहेज किया, उनके 42% विज्ञापनों में उन लक्षित राज्यों के चुनाव-क्षेत्रों को छोड़कर, जहां पहले चरण में मतदान हुआ था।
- 19 अप्रैल को राजस्थान, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को इन राज्यों में कांग्रेस के विज्ञापनों से बाहर रखा गया था।
- मध्य प्रदेश में, सीधी को छोड़कर सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को कांग्रेस के विज्ञापनों से बाहर रखा गया था।
- भाजपा के विपरीत, कांग्रेस ने अपने लक्षित विज्ञापनों में विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मौन अवधि के दौरान पूरे मणिपुर में उपस्थिति बनाए रखी।

मेटा अभियान

- चुनाव के पहले चरण के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के आधार पर मेटा प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम और फेसबुक) पर विज्ञापन अभियान चलाया।
- Google विज्ञापनों के विपरीत, मेटा विज्ञापन पिन कोड-विशिष्ट नहीं थे, बल्कि राज्य-विशिष्ट थे, जो पहले चरण में शामिल निर्वाचन क्षेत्रों सहित पूरे राज्यों को कवर करते थे।
- बीजेपी ने कई राज्यों को लक्ष्य करते हुए मेटा पर 6,808 विज्ञापन पोस्ट किए, जबकि कांग्रेस ने 114 विज्ञापन पोस्ट किए, जिनमें मुख्य लक्ष्य तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश थे।
- पोस्ट किए गए विज्ञापनों की संख्या में भाजपा स्पष्ट रूप से आगे थी और कांग्रेस की तुलना में उसका अभियान अधिक विविध था, जो इस्तेमाल की गई भाषाओं से स्पष्ट है। भाजपा ने सात से अधिक भाषाओं में विज्ञापन पोस्ट किए, जबकि कांग्रेस ने केवल तीन भाषाओं में विज्ञापन पोस्ट किए।
- राजनीतिक दलों को डिजिटल मीडिया विज्ञापन अभियानों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की सीमाओं को बढ़ाते हुए देखा गया, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।
- डिजिटल अभियानों में स्थान-आधारित लक्ष्यीकरण ने पार्टियों को प्रतिबंधित अभियान अवधि के दौरान मतदाताओं तक पहुंचने की अनुमति दी, जिससे संभावित रूप से एमसीसी नियमों को दरकिनार किया गया।
- जैसे-जैसे चुनाव का दूसरा चरण नजदीक आ रहा है, एमसीसी के पालन के संबंध में टिप्पणियाँ विचार करने योग्य हो सकती हैं।

PatrioticIAS

'बढ़ती गर्मी से महंगाई की आशंका (24 अप्रैल)

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों ने चरम मौसम की घटनाओं के मुद्रास्फीति पर असर पड़ने के संभावित जोखिम के बारे में आगाह किया है।
- मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.9% थी, जो पिछले दो महीनों के औसत 5.1% से थोड़ा कम है।
- निकट अवधि में चरम मौसम की घटनाओं के साथ-साथ लंबे समय तक भूराजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने अपनी "स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023" रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 2024 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष बनने की उच्च संभावना का सुझाव दिया गया है।
- डब्ल्यूएमओ के अनुसार, जैसे-जैसे दुनिया गर्म तापमान की ओर बढ़ रही है, मीठे पानी की कमी के संकट पर चिंता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग का डेटा चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि का संकेत देता है, जिसके लिए तत्काल और सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों ने जून के बाद ला नीना की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, गंभीर पूर्वानुमानों के बीच आशा का उल्लेख किया, जो भारत में भारी वर्षा ला सकता है।
- ला नीना के कारण आमतौर पर भारत में औसत से अधिक वर्षा होती है, जिससे पानी की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों को राहत मिलती है।
- उन्होंने जनवरी 2024 के बाद से हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी का उल्लेख करते हुए हालिया मुद्रास्फीति की गतिशीलता को भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं के लिए सकारात्मक बताया।
- मार्च में मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर नरम होने का श्रेय सभी वस्तुओं और सेवाओं के घटकों में नरमी को दिया गया।
- यह प्रवृत्ति आरबीआई द्वारा लागू अवस्फीतिकारी मौद्रिक नीति उपायों की प्रभावशीलता का समर्थन करती है।

विकल्प 1: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

- **आर्थिक संकेतक:** पीएमआई एक समग्र संकेतक है जो देश के विनिर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य को मापता है। यह विनिर्माण कंपनियों में क्रय प्रबंधकों के बीच किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है।
- **घटक:** पीएमआई में आम तौर पर पांच उप-सूचकांक शामिल होते हैं:
  - नए आदेश
  - उत्पादन स्तर
  - रोज़गार
  - आपूर्तिकर्ता डिलीवरी
  - सूची
- **व्याख्या:**
  - पीएमआई का 50 से ऊपर रहना विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार का संकेत देता है।
  - पीएमआई का 50 से नीचे रहना क्षेत्र में संकुचन का संकेत देता है।
  - पीएमआई = 50 कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।
- **महत्व:** अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा समग्र आर्थिक गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक के रूप में पीएमआई का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता है।

PatriotIAS

विकल्प 2: परियोजना प्रबंधन संस्थान (पीएमआई)

- **वैश्विक व्यावसायिक संगठन:** पीएमआई परियोजना प्रबंधन पेशेवरों के लिए दुनिया का अग्रणी गैर-लाभकारी संगठन है।
- **मिशन:** विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, प्रमाणपत्रों, संसाधनों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परियोजना प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाना।
- **प्रमाणपत्र:** पीएमआई कई प्रसिद्ध प्रमाणपत्र प्रदान करता है जिनमें शामिल हैं:
    - प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल (पीएमपी)®
    - प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रमाणित एसोसिएट (CAPM)®
    - अनुशासित चंचल प्रमाणपत्र
- **मानक और संसाधन:** पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज (पीएमबीओके® गाइड) और अन्य मानक, ढांचे और प्रकाशन विकसित करता है।
- **समुदाय:** पीएमआई परियोजना प्रबंधकों के लिए जुड़ने, सीखने और ज्ञान साझा करने के लिए एक वैश्विक समुदाय बनाता है।

विनिर्माण क्षेत्र पर सतत भारतीय दृष्टिकोण की एक आलोचनात्मक परीक्षा (24 अप्रैल)

- 77 वर्षों से अधिक समय से, भारत के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग ने विनिर्माण को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में महत्व दिया है।
- कारणों में अधिक उत्पादकता, रोजगार सृजन और तीव्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की उम्मीदें शामिल हैं।
- लुईस टू-सेक्टर मॉडल जैसे आर्थिक मॉडल सुझाव देते हैं कि कृषि से अधिशेष श्रम को अधिक उत्पादक कार्यों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- आधुनिक क्षेत्र की विशेषता पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियां और उच्च स्तर का पूंजी निवेश है।
- भारत में विनिर्माण विकास के समर्थकों का तर्क है कि कृषि क्षेत्र कम उत्पादक है, क्षेत्रों के बीच श्रम गतिशीलता संभव है, और भारत को विनिर्माण में तुलनात्मक लाभ है।
- कुछ आवाजें विनिर्माण विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रमिक अधिकारों और भूमि अधिग्रहण पर नियमों को आसान बनाने का सुझाव देती हैं।
- हालाँकि, इन दावों की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए इनकी आलोचनात्मक जाँच आवश्यक है।
- कृषि उत्पादकता के संबंध में पहला दावा जटिल है और इसके लिए विशेष परीक्षण की आवश्यकता है।
- 2012 से 2022 तक, प्रति हेक्टेयर अनाज की पैदावार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई।
- श्रम बल में उनकी घटती हिस्सेदारी के बावजूद, इसी अवधि के दौरान कृषि में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 10 मिलियन से अधिक बढ़ गई।

मूल्य वर्धित वृद्धि

- भारत के कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्रति श्रमिक जोड़ा गया मूल्य 2012 और 2022 के बीच 1,557 डॉलर से बढ़कर 2,400 डॉलर हो गया, जो अधिक श्रम को अवशोषित करने के बावजूद उत्पादकता में वृद्धि का संकेत देता है ।
- यह दावा कि कृषि क्षेत्र पूरी तरह से कम उत्पादक है, गलत हो सकता है क्योंकि इसने प्रति श्रमिक बेहतर उत्पादन दिखाया है।
- उत्पादकता पर बाधाएं केवल श्रमिकों की अधिकता से ही नहीं, बल्कि पूंजी और तकनीकी सीमाओं से भी उत्पन्न होती हैं।

PatriotIAS

- श्रम गतिशीलता की आसानी पर विवाद हुआ है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारतीय विनिर्माण श्रमिक अपने वैश्विक समकक्षों की तरह योग्य नहीं हो सकते हैं।
- तुलनात्मक लाभ के रिकार्डियन सिद्धांत से पता चलता है कि निर्यात में सफल विशेषज्ञता के लिए, किसी देश को अन्य देशों की तुलना में अच्छे उत्पादन की अवसर लागत कम करनी चाहिए।
- "मेक इन इंडिया" पहल के तहत, सरकार ने व्यापार करने में आसानी सूचकांक रैंकिंग में सुधार करके और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं और सब्सिडी की पेशकश करके विदेशी उद्यमों को आकर्षित करने के प्रयास किए हैं।
- इन प्रयासों के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान स्थिर बना हुआ है, 1960 के दशक में 13-16% की तुलना में 2022 में 13% और 1979 में 18% पर पहुंच गया।
- भारत में विनिर्माण को खराब बुनियादी ढांचे, कुशल श्रमिकों की कमी और न्यूनतम अनुसंधान और विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके तुलनात्मक लाभ में बाधा बन सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में विनियमन और आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में विनिर्मित वस्तुओं की मांग में कमी को ध्यान में रखना चाहिए।
- इसके विपरीत, भारत के सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सेवाओं का मूल्य 1960 के दशक में 38% से बढ़कर 2022 में 48% से अधिक हो गया है।
- भारत ने सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता दिखाई है, विशेषकर अपनी शिक्षित आबादी के कारण।
- डॉ. राजन जैसे अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एकल चिप फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करना संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो सकता है।
- इसके बजाय, साक्षरता दर बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा में सुधार जैसी पहलों के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- विनिर्माण क्षेत्र में अधिकांश मूल्यवर्धन, जैसे कि मोबाइल फोन, मालिकाना डिज़ाइन तकनीक से आता है, जिसका स्वामित्व अक्सर विदेशी कंपनियों के पास होता है।
- असेंबली के बजाय डिज़ाइन के माध्यम से मूल्यवर्धन का अधिक हिस्सा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक फायदेमंद हो सकता है।
- चिप्स जैसे उत्पादों में डिजाइन में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, जो डिजाइन में तुलनात्मक लाभ का संकेत देती है।
- विनिर्माण क्षेत्र से सेवाओं और शिक्षा में मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए निवेश को पुनर्निर्देशित करने से विनिर्माण प्रोत्साहन के साथ शुरू में की गई कल्पना की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकता है।

PatrioticIAS

प्रश्न 1: नीलगिरि तहर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है? (ए) हिमालय (बी) अरावली रेंज (सी) पश्चिमी घाट (डी) पूर्वी घाट	उत्तर: (सी) पश्चिमी घाट व्याख्या : नीलगिरि तहर पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, इसकी सीमा दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम नीलगिरि पर लागू होता है तहर ?	उत्तर: (डी) 1, 2, और 3

1. तमिलनाडु का राज्य पशु 2. IUCN लाल सूची स्थिति: लुप्तप्राय 3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची। (ए) केवल 1 और 2 (बी) केवल 2 और 3 (सी) केवल 1 और 3 (डी) 1, 2, और 3	व्याख्या : नीलगिरि तहर को तमिलनाडु के राज्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो इसकी कमजोर जनसंख्या स्थिति को दर्शाता है। नीलगिरि को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है तहर .
नीलगिरि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तहर : 1. यह एक शाकाहारी जानवर है जो ऊंचाई वाले घास के मैदानों में रहता है। 2. यह बाघ और तेंदुए जैसे शिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिकार प्रजाति है। 3. उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (ए) केवल 1 **स्पष्टीकरण:** **कथन** 1 सही है. **कथन** 2 गलत है - तेंदुए और ढोल नीलगिरि के संभावित शिकारी हैं तहर ; बाघ आमतौर पर इसके उच्च ऊंचाई वाले आवास में नहीं पाए जाते हैं।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरि का प्रमुख निवास स्थान है तहर ? (ए) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (बी) एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (सी) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (डी) गिर राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर: (बी) एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान **स्पष्टीकरण:** केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरि की महत्वपूर्ण आबादी के लिए प्रसिद्ध है tahrs .
प्रश्न 5: हिमानी झीलों के निर्माण का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? (ए) ज्वालामुखी विस्फोट (बी) ग्लेशियरों का पीछे हटना (सी) टेक्टोनिक प्लेट आंदोलन (डी) तटीय कटाव	उत्तर: (बी) ग्लेशियरों का पीछे हटना **व्याख्या:** जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं और पीछे हटते हैं, पीछे छूटे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे हिमनद झीलें बन जाती हैं।
प्रश्न 6: हिमानी झीलें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष चिंता का विषय हैं? (ए) भारतीय मैदान (बी) उष्णकटिबंधीय वर्षावन (सी) हिमालय क्षेत्र (डी) तटीय क्षेत्र	उत्तर: (सी) हिमालय क्षेत्र **स्पष्टीकरण:** हिमालय में बड़ी संख्या में ग्लेशियर हैं, और उनके पीछे हटने से हिमनद झीलों का निर्माण बढ़ जाता है, जिनमें से कुछ खतरे में हैं।
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी झीलों से जुड़ा संभावित खतरा है? (ए) ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) (बी) सुनामी (सी) जैव विविधता में कमी (डी) मिट्टी का लवणीकरण	उत्तर: (ए) ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) **स्पष्टीकरण:** जीएलओएफ तब होता है जब हिमनद झीलों को रोकने वाले प्राकृतिक बांध विफल हो जाते हैं, जिससे अचानक और संभावित रूप से विनाशकारी पानी नीचे की ओर छोड़ा जाता है।
प्रश्न 8: हिमानी झीलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वे मीठे पानी के भंडार के रूप में कार्य कर सकते हैं।	उत्तर: (डी) 1, 2, और 3 **स्पष्टीकरण:** तीनों कथन सही हैं। हिमनद झीलें जल संसाधनों, आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती हैं।

PatrioticIAS

2. वे GLOFs के कारण प्राकृतिक आपदाओं का खतरा पैदा करते हैं। 3. ये जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? (ए) केवल 1 और 3 (बी) केवल 2 और 3 (सी) केवल 1 और 2 (डी) 1, 2, और 3	
प्रश्न 9: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-लेह (LAHDC लेह) किस क्षेत्र के शासन के लिए जिम्मेदार एक निर्वाचित निकाय है? (ए) कश्मीर घाटी (बी) लेह जिला, लद्दाख (सी) तवांग , अरुणाचल प्रदेश (डी) लाहौल- स्पीति , हिमाचल प्रदेश	उत्तर: (बी) लेह जिला, लद्दाख स्पष्टीकरण: LAHDC लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर लेह जिले के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है।
प्रश्न 10: संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों की स्थापना की? (ए) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (बी) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1995 (सी) पंचायती राज अधिनियम, 1992 (डी) भारत सरकार अधिनियम, 1935	उत्तर: (बी) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1995 **स्पष्टीकरण:** LAHDC लेह और कारगिल में इसके समकक्ष की स्थापना एक विशिष्ट अधिनियम के तहत की गई थी जो लद्दाख में विकेंद्रीकृत शासन पर केंद्रित है।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा विषय LAHDC लेह के दायरे में आता है? 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य 2. शिक्षा 3. पर्यटन (ए) केवल 1 और 2 (बी) केवल 2 और 3 (सी) केवल 1 और 3 (डी) 1, 2, और 3	उत्तर: (डी) 1, 2, और 3 **स्पष्टीकरण:** एलएएचडीसी लेह के पास लेह जिले की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सूचीबद्ध सहित कई विषयों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
प्रश्न 12: LAHDC लेह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी पार्षद करता है। 2. इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों **स्पष्टीकरण:** एलएएचडीसी की संरचना और उसके नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व के लिए नामांकित सदस्यों को शामिल करना दोनों सटीक हैं।
प्रश्न 13: जीका वायरस मुख्य रूप से फैलता है: (ए) मच्छर का काटना (बी) दूषित भोजन (सी) हवाई बूंदें (डी) संक्रमित तरल पदार्थ के साथ सीधा संपर्क	उत्तर: (ए) मच्छर का काटना **स्पष्टीकरण:** जीका के संचरण का प्राथमिक तरीका संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से होता है।

PatrioticIAS

प्रश्न 14: गर्भवती महिलाओं में जीका संक्रमण से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य जटिलता निम्नलिखित में से कौन सी है? (ए) गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (बी) नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली (सी) डेंगू बुखार (डी) हेपेटाइटिस बी	उत्तर: (बी) नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली **स्पष्टीकरण:** गर्भावस्था के दौरान जीका संक्रमण माइक्रोसेफली से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी स्थिति जहां बच्चे सामान्य से छोटे सिर के साथ पैदा होते हैं और संभावित विकास में देरी होती है।
प्रश्न 15: जीका वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग प्रदर्शित करते हैं: (ए) गंभीर बुखार, दाने और जोड़ों का दर्द (बी) रक्तस्रावी लक्षण (सी) श्वसन संकट (डी) हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं	उत्तर: (डी) हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं **स्पष्टीकरण:** जीका संक्रमण का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत स्पर्शोन्मुख होता है या केवल बुखार, दाने और नेत्रश्लेष्मलाशोथ जैसे हल्के लक्षण दिखाता है।
प्रश्न 16: जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसकी पहचान सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी। 2. वर्तमान में जीका के लिए एक टीका उपलब्ध है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (ए) केवल 1 **स्पष्टीकरण:** कथन 1 सही है. जीका वायरस को सबसे पहले युगांडा के जीका वन में अलग किया गया था। कथन 2 गलत है. हालांकि शोध जारी है, जीका वायरस के लिए वर्तमान में कोई व्यापक रूप से उपलब्ध टीका नहीं है।
प्रश्न 17: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई) एक वैश्विक संगठन है जो इसके लिए जाना जाता है: (ए) परियोजना प्रबंधन के लिए उद्योग मानक निर्धारित करना (बी) परियोजना प्रबंधन में पेशेवर प्रमाणपत्र प्रदान करना (सी) परियोजना प्रबंधन में अनुसंधान और वकालत को बढ़ावा देना (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी **स्पष्टीकरण:** पीएमआई सूचीबद्ध सभी पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसे विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

PatrioticIAS